

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 469]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 30, 1972/कार्तिक 8, 1894

No. 469]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 30, 1972/KARTIKA 8, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 30th October 1972

S.O. 684(E)/18A/IDRA/72.—Whereas the Central Government is of the opinion that the Suraj Textile Mills Limited, Malout Mandi, (Punjab), an industrial undertaking in respect of which an investigation has been made under section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) is being managed in a manner highly detrimental to public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 18-A of the said Act, the Central Government hereby authorises the National Textile Corporation Limited, (hereinafter referred to as Authorised Controller) to take over the management of the whole of the said undertaking, namely the Suraj Textile Mills Limited, Malout Mandi subject to the following terms and conditions, namely:—

- (i) The Authorised Controller shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government.
- (ii) The Authorised Controller shall hold office for five years from the date of publication in the official gazette of this notified order.
- (iii) The Central Government may terminate the appointment of the Authorised Controller earlier, if it considers it necessary to do so.

This Order shall have effect for a period of five years commencing from the date of its publication in the Official Gazette.

[No. F. 3/42/72/CUC.]

K. S. BHATNAGAR, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली 30 अक्टूबर, 1972

का० आ० 684(अ)/18ए/आई डी आर ए/72.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि सूरज टैक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, मलौट मंडी, (पंजाब), औद्योगिक उपक्रम का, जिसकी बाबत उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 के अधीन अनुवेष्टन किया जा चुका है, प्रवन्ध इस रीति से किया जा रहा है कि लोकहित में अति अहितकर हैं।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 18-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि०, को (जिसे इसमें सके पश्चात् प्राधिकृत नियन्त्रक कहा गया है) उक्त उपक्रम, अर्थात् सूरज टैक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, मलौट मंडी का पूर्ण प्रवन्ध निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए ग्रहण करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

- (1) प्राधिकृत नियन्त्रक केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गए सभी निदेशों का पालन करेगा।
- (2) प्राधिकृत नियन्त्रक राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से 5 वर्ष के लिए पदासीन रहेगा :
- (3) केन्द्रीय सरकार, प्राधिकृत नियन्त्रक को नियुक्ति यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो, पहले ही समाप्त कर सकेगी।

यह आदेश शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा।

[सं० फा० 3/42/72—सी यू सी]

के० एम० भटनागर, संयुक्त सचिव।